KUMARI MAMATA BANERJEE: Sir, there are so many projects on various things and unmanned level crossing is also a part of it. At that time, 25,000 unmanned railway crossings were there. But, during these years, it is now only 16,000. It is because funds are being spent on it from the Safety Fund. When, I again became the Railway Minister, I found that there were about 16,000 unmanned railway crossings. You will be happy to know that we have already taken up 4,000 unmanned railway crossings. So, right now, there are only 12,000 unmanned railway crossings. According to our Vision Document, these 12,000 unmanned railway crossings would also be completed in three-four years. And, we will complete the signaling of these unmanned level crossings within two years.

Incidence of dacoity in running trains

*387. SHRI MAHENDRA MOHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether dacoits in police uniforms and equipped with arms etc. are looting commuters in running trains;

(b) if so, the details of such incidents which have come to the notice of Railways;

(c) whether Railway Protection Force has completely failed to protect commuters from dacoits and anti-national elements in running trains; and

(d) if so, the steps Government proposes to take to prevent such crimes on running trains?

THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) No, Sir. No such incident has been reported.

(c) and (d) 'Policing on Railways' is a State subject and prevention of crime, registration of cases and their investigation and maintenance of law and order in Railway premises as well as on running trains are the statutory responsibility of the State Governments concerned which they

discharge through the Government Railway Police (GRP) and Civil Police. Railways bear 50% cost of expenditure on the Government Railway Police. As such Railway has to depend largely on the State Governments. RPF does not have any legal power to prosecute the offenders involved in criminal offences like dacoity/ robbery/ theft of passengers' belongings, drugging etc.

However, to provide better security to the travelling passengers in trains and passenger areas, the RPF Act, 1957 and the Railways Act, 1989 have been amended in the year 2003 to enable the Railways through the Railway Protection Force, to supplement the efforts of the State Governments in controlling crime on the Railways and for maintenance of law and order. RPF have been empowered to deal with 29 minor offences such as roof travelling, alarm chain pulling, touting, ticket less travel, unauthorized entry in ladies compartment etc. after modifying the Railways Act 1989, so that GRP can spare more time and manpower to prevent and detect heinous offences like Murder, Dacoity/ Robbery, Rape etc.

In addition to the above, the following measures are being taken by the Railways for the security of passengers:-

1. 1275 trains are escorted by Railway Protection Force daily on an average, in addition to escorting of 2200 trains by Government Railway Police of different States.

2. The Ministry of Railways has been closely coordinating with the State Governments for prevention and detection of crimes on Railways and maintenance of law and order.

3. A coordination meeting with the State Home Secretaries, officials of Ministry of Home Affairs, Intelligence Bureau and Railways was held on 20.01.2010 at Rail Bhavan, New Delhi.

4. Regular coordination meetings are being conducted with GRP and Civil Police by Railways at Zonal and Divisional level to review the crime position in Railways.

5. Regular announcements at important stations are made to create awareness among the travelling public about passenger offences, especially about cases of drugging.

6. An amendment in the RPF Act is under examination to enable RPF to deal with the passenger related offences more effectively.

श्री महेन्द्र मोहन : धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसमें लिखा है कि डकैती की कोई भी घटना नहीं हुई है और उनकी जानकारी में भी नहीं है। अभी हाल ही में 6 अगस्त को कलकत्ता-दिल्ली एक्सप्रेस-3111 अप में बिहार में डकैती पड़ी, 21 आदमी घायल हुए जिसमें जी.आर.पी.एफ. का स्टाफ भी था। 8 अगस्त को हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस-3049 अप में जेसीडी और झाझा रूट पर डकैती पड़ी, जिसमें 3 पैसेंजर्स को मारा व लूटा गया और डेढ़ लाख रुपये की लूट हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि आए दिन रेलगाड़ियों में डकैतियां पड़ रही हैं, लूटमार हो रही है और उसके बाद अगर यह उत्तर दिया जाता है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि यात्रियों को लूटने, ठगने, जहर खुरानी, स्नेचिंग तथा अन्य जो भी घटनाएं होती हैं उनकी एफ.आई.आर. क्यों नहीं दर्ज होती है और अगर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा रही हैं तो इसके क्या कारण हैं और सरकार किस प्रकार से जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसको यह अधिकार देने जा रही है कि इन डकैतियों की, इन लूटमार की समाप्ति हो? क्योंकि, आजकल यह पाया जा रहा है कि रेलवे में चलना बहुत ही जोखिम भरा होता चला जा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इसमें वह क्या सुधार करने जा रही है और कानून में क्या परिवर्तन ला रही है?

कुमारी ममता बनर्जी : सर, माननीय सदस्य का क्वेश्चन था कि क्या पुलिस यूनिफार्म पहनकर डकैती की जा रही है या नहीं? तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई इंफार्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर जी.आर.पी.एफ. ने कुछ किया हो तो स्टेट पुलिस है। जी.आर.पी.एफ. जो रेलवे में पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स है, RPF is different form the GRPF. लेकिन आपने जी.आर.पी.एफ. का नाम लिया है, जी.आर.पी.एफ. तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन The Railways give 50% salary to them. The State Government also gives 50%. So, they take care of it. हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस ड्रेस पहनकर कोई डकैती हुई है। क्योंकि यह सेंसेटिव सब्जेक्ट भी है अगर पुलिस की ड्रेस पहनकर कोई चीज होती है तो यह अनकांस्टीट्यूशनल है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमको दीजिए।

श्री महेन्द्र मोहन : सभापति जी, जो जानकारी मिली है, जो अखबारों में सूचनाएं मिलती हैं उसमें तो यही जानकारी है कि पुलिस वर्दी वगैरह में लोग जाते हैं। जो माननीय मंत्री जी कह रही हैं, वही मैं भी कह रहा हूं कि उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में और भी कहा है कि यात्रियों से

जुड़ी वारदातों में अधिक कारगर कार्रवाई करने में रेल सुरक्षा बल को समर्थ बनाने के लिए आर.पी.एफ. एक्ट में संशोधन करने की जांच की जा रही है। यह जानकर प्रसन्नता है कि जांच की जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, आर.पी.एफ. को कब यह अधिकारी मिलेंगे और इतनी जो घटनाएं डकैती आदि की हुई हैं उसमें जो कोआर्डिनेशन स्टेट पुलिस के साथ होता है, उसमें क्या घटनाएं हुई हैं और स्टेट पुलिस से क्या कोई रिपोर्ट मिली हैं कि उन घटनाओं में क्या प्रगति हुई है, कोई अपराधी पकड़े गए हैं अथवा नहीं?

कुमारी ममता बनर्जी : हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंटीन्यूअस परस्यू करते हैं कि लॉ एंड आर्डर को प्रोटेक्शन दीजिए, Law and order is a State subject. आप प्रोटेक्शन दीजिए। हम इसको परस्यू करते हैं। लेकिन आपने बोला है कि पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? हम स्टेट गवर्नमेंट नहीं हैं, हम कैसे कार्रवाई करेंगे, स्टेट पुलिस के खिलाफ कार्रवाई तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, हम कैसे कर सकते हैं। उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की अथॉरिटी रेल की नहीं है। दूसरी बात, आर.पी.एल. के बारे में आपने जो पूछा है ...(**व्यवधान**)...

श्री राम कृपाल यादव : लगातार बिहार में डकैतियां हो रही हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बैठ जाइए, जवाब तो सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

KUMARI MAMTA BANERJEE : If Parliament allows the RPF to do it. ...*(Interruptions)*... because it is a law and order problem, then, we will be happy to do it. ...*(Interruptions)*...

श्री राम कृपाल यादव : मैडम को तो पता ही होगा कि वहां पर कितनी घटनाएं हुई हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Structural framework for national food security

†388. SHRI KALRAJ MISHRA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

---

†Original notice of the question was received in Hindi.